

मुकदमों का विवरण

मानाक चंद @मणि बनाम।

हरियाणा राज्य

(2014 की आपराधिक अपील संख्या 2276) 30 अक्टूबर, 2023

[संजय किशन कौल, सी. टी. रविकुमार और सुधांशु धूलिया, जे. जे.]

हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या निचली अदालतों को बलात्कार के अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराने और सजा देने में न्यायसंगत ठहराया गया था। 376 भारतीय दंड संहिता .

दंड संहिता, **1860** -धारा **376**-बलात्कार-**16** वर्ष से कम आयु के अभियोजक का आरोप, उसकी बहन के बहनोई-अपीलार्थी के खिलाफ कि जब वह अपनी बहन के वैवाहिक घर गई थी तो उसके साथ दो बार तीन बार बलात्कार किया गया था-पारिवारिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए, शुरू में मामले को दोनों की शादी से निपटाने की मांग की गई थी-हालांकि, ऑफ एर को अस्वीकार कर दिया गया था, और अभियोजक के पिता ने एक प्राथमिकी दर्ज की-अपीलार्थी को दोषी ठहराने का आदेश और सजा। **376** निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा-शुद्धता

आयोजित किया गया: अभियोजक की गवाही विश्वास को प्रेरित नहीं करती है-उसने तुरंत घटना का खुलासा नहीं किया, बल्कि दो तीन मौकों पर बलात्कार के आरोप थे, लेकिन कोई तारीख या समय का खुलासा नहीं किया गया-उसने डेढ़ महीने के बाद अपनी माँ को घटना के बारे में बताया-जिस तारीख को अभियोजक ने बलात्कार की पहली घटना का आरोप लगाया था, वही तारीख थी, अभियोजन पक्ष ने सबूत का नेतृत्व किया कि वह एक अलग स्थान पर स्थित स्कूल में पढ़ती थी-यह असंभव लगता है, अगर असंभव नहीं है-साथ ही एफ़. आई. आर. अंततः शुरू हो गई क्योंकि शादी के प्रारंभिक प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था-इन सभी तथ्यों ने अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा कर दिया-सबूत, उम्र के बारे में या यहाँ तक कि बलात्कार के बारे में भी नीचे की अदालतों द्वारा ठीक से जांच नहीं की गई-कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल सकता था।

अपराध के कथित कार्य के समय आयु-इसके अलावा, अभियोजन पक्ष अभियोजक की आयु के निर्धारण के लिए अस्थि अस्थार्ई परीक्षण करने में विफल रहा-इस प्रकार, अपीलार्थी को लाभ दिया जाना चाहिए-जहां तक बलात्कार के तथ्य का संबंध है, बलात्कार का अपराध नहीं बनाया गया क्योंकि यह बलात्कार के घटकों को पूरा नहीं करता था जैसा कि यू/एस के रूप में माना जाता है।³⁷⁵, क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह पता चले कि अपीलार्थी ने अभियोजक के साथ यौन संबंध बनाए थे, लेकिन यह उसकी इच्छा के खिलाफ या उसकी सहमति के बिना था-इस प्रकार, निचली अदालतों के आदेश को दरकिनार कर दिया गया और अपीलार्थी को आरोपों से बरी कर दिया गया।[पैरा 6,9,11 और 12]

साक्ष्य-बलात्कार का अपराध-अभियोजन पक्ष की गवाही-साक्ष्य मूल्य:

आयोजित किया गया:अभियोजक की एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है-न्यायालय ों को इस एकमात्र गवाही की जांच करते समय बेहद सावधानी बरतनी होगी-इसके अलावा, अभियोजक के साथ-साथ अभियुक्त दोनों को निष्पक्ष मुकदमे का अधिकार है-इस प्रकार, जब अभियोजक का बयान विश्वास को प्रेरित नहीं करता है और संदेह पैदा नहीं करता है, तो न्यायालय को पुष्टिकारक साक्ष्य की तलाश करनी चाहिए।[पैरा 5]

साक्ष्य-बलात्कार का मामला-अस्थि ऑसिफ़ाई कैशन परीक्षण-आवश्यकता:

आयोजित किया गया:ऐसे मामलों में, अभियोजक की उम्र के बारे में कुछ विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हड्डी ऑसिफ़ाई कैशन परीक्षण की आवश्यकता होती है।

[पैरा 9]

आपराधिक न्यायशास्त्र-मार्गदर्शक सिद्धांत:

आयोजित किया गया:अदालतों को प्रत्येक साक्ष्य की खुले दिमाग से निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए क्योंकि एक आरोपी को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाना चाहिए-मार्गदर्शक सिद्धांत हमेशा ब्लैकस्टोन अनुपात होगा जिसमें कहा गया है कि एक निर्दोष को दंडित करने की तुलना में दस दोषी व्यक्तियों का भाग जाना बेहतर है।[पैरा 7]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह, (1996) 2 एससीसी 384:[1996] 1 एससीआर

532; सदाशिव रामराव हदबे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2006) 10 एस. सी. सी. 92; राजू और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2008) 15 एस. सी. सी. 133:[2008] 16 एस. सी. आर. 1078; बिराद मल सिंघवी बनाम आनंद पुरोहित (1988)

एस. सी. सी. 604-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता :2014 की आपराधिक अपील No.2276।

2001 के सी. आर. ए. एस. No.1051 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

जय किशोर सिंह, मोहित राज, हेमंत शर्मा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।समर विजय सिंह, संजय कुमार त्यागी, केशव मित्तल, सबरनी सोम, अमन देव शर्मा, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

सुधांशु धूलिया, न्या .

1. इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (इसके बाद 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है और उसे डिफॉल्ट शर्तों के साथ सात साल के आर. आई. और Rs.1000 की सजा सुनाई गई है।पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपील में 19.02.2014 के निर्णय के अनुसार निचली अदालत के दिनांक 03.09.2001 के आदेश को बरकरार रखा है।

2. ज्ञान चंद (शिकायतकर्ता) द्वारा 23.10.2000 पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जो अपीलार्थी के बड़े भाई पप्पु के ससुर हैं।इसमें कहा गया है कि 02.09.2000 पर, पप्पु ने शिकायतकर्ता से अपनी छोटी बेटी (जो वर्तमान अभियोजक है) को अपनी बहन की देखभाल के लिए अपने घर भेजने का अनुरोध किया, जिसने अभी-अभी एक लड़की को जन्म दिया था।यह आरोप लगाया जाता है कि संबंधित समय में अभियोजक की आयु 15 वर्ष थी।अभियोजक को उसके पिता ने उसकी बहन के वैवाहिक घर में कुछ समय के लिए रहने के लिए भेजा था।एक महीने से भी अधिक समय बाद, अभियोजक अपने घर लौटा, उसकी माँ को बताता है कि जब वह अपनी बहन के घर में थी, तो वर्तमान अपीलकर्ता मानक चंद उर्फ मणि, जो पप्पु का छोटा भाई है, ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद दो से तीन बार ऐसा ही दोहराया।प्रारंभ में, 77 पर विचार किया जा रहा है।

मानक चंद @मणि बनाम हरियाणा राज्य [सुधानशु धूलिया, जे.] 78 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

परिवारों के बीच संबंध, मामला "सुलझा" जा रहा था, और दोनों परिवार अपीलार्थी मानक चंद उर्फ मणि के साथ अभियोजक की शादी के लिए भी सहमत हो गए थे।लेकिन यह आरोप लगाया जाता है कि अपीलार्थी के परिवार ने बाद में आई. डी. 1 को अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376,342 और 506 के अंतर्गत

पुलिस स्टेशन सिटी डबवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई। संक्षेप में यह अभियोजन पक्ष का मामला है।

3. जाँच के बाद, आई. डी. 1 पर आरोप पत्र दायर किया गया और मामला उन सत्रों के लिए प्रतिबद्ध था जहाँ अपीलार्थी/अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 और 506 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए थे। अभियोजन पक्ष ने 7 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें पीडब्लू-5 भी शामिल था, जो अभियोजक था।

अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि घटना की तारीख को अभियोजक नाबालिग था। इसे साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने स्कूल रजिस्टर में 04.04.1987 के रूप में दर्ज अभियोजक की जन्म तिथि पर भरोसा किया। पीडब्लू-5 अर्थात्, 17.04.2001 पर विचारण न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजक का कहना है कि वह अपनी बहन के साथ रहने गई थी, जब उसकी "जीजा" (जीजा) द्वारा उसे मदद के लिए उनके घर भेजने का अनुरोध किया गया था। 12.09.2000 पर, जब उसकी बहन घर से दूर थी और अभियोजक अकेला था, तो अपीलकर्ता उसके कमरे में आया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, उसे एक चाकू दिखाया और उसकी शारीरिक इच्छाओं के आगे नहीं झुकने पर उसे जान से मारने की धमकी दी; और फिर उसके साथ बलात्कार किया। वह आगे कहती है कि उस घटना के बाद, अपीलार्थी ने अभियोजक पर दो या तीन अलग-अलग मौकों पर एक ही कार्य किया। फिर वह अपने मायके लौटती है और अपनी माँ सीता देवी/सीतो बाई को घटना के बारे में बताती है, जो बलात्कार की घटना के एक महीने से अधिक समय बाद हुई है। उनके पिता ज्ञान चंद (पीडब्लू-6) ने भी उनके बयान का समर्थन किया। वह कहता है कि यह जानकारी मिलने पर वह अपने दामाद पप्पु के घर गया और उसे पूरी घटना सुनाई, जैसा कि उसकी बेटी ने उसे बताया था। इसके बाद उन्होंने अपीलार्थी के माता-पिता के समक्ष अपीलार्थी मानक चंद उर्फ मणि के साथ अभियोजक की शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन चूंकि उसे कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया, इसलिए उसने 23.10.2000 पर प्राथमिकी दर्ज की।

पीडब्लू-1 डॉ. कुलविंदर कौर ने 11.30 ए. एम. पर 28.10.2000 पर अभियोजक की चिकित्सकीय जांच की। पीडब्लू-1 में कहा गया है कि अभियोजक की आयु, जैसा कि अभियोजक की माँ ने उसे बताया था, 16 वर्ष थी और अभियोजक की चिकित्सा जांच का विवरण इस प्रकार था:

“सामान्य परीक्षा: पूरी तरह से निर्मित वयस्क महिला

सचेत, मध्यम रूप से पोषित। स्तन, गर्दन, चेहरे, पेट और जांघ पर चोट का कोई बाहरी निशान नहीं था।

स्थानीय परीक्षा: उसके सार्वजनिक बाल अच्छी तरह से विकसित थे; बाहरी जननांग पूरी तरह से विकसित और सामान्य थे। चोट का कोई बाहरी निशान नहीं था।

प्रति टीकाकरण परीक्षा:लैबिया मिनोरा को हाइपरट्रॉफी किया गया था,

हाइमेन टूट गया था 2 फिंगर स्वीकार किया गया था।योनि में और उसके आसपास तीव्र सूजन का कोई संकेत नहीं था।वहाँ निर्वहन था।गर्भाशय नॉन ग्रेविड, फाईआरएम और मोबाइल और फोर्निक्स लोमड़ी निशुल्क ।

उसकी योनि का स्वाब नहीं लिया गया क्योंकि पं. को 5 दिन पहले मासिक धर्म हुआ था और हमले का इतिहास डेढ़ दो महीने पहले का है।Ex.PB एम. एल. आर. की वास्तविक प्रति में। सबसे पहले, अभियोजक की उम्र उसकी माँ की जानकारी पर 15 दर्ज की गई थी जिसे बाद में सुधार कर 16 वर्ष कर दिया गया था।यह भी अभियोजक की माँ की जानकारी पर किया गया था।

रोगी की चिकित्सीय जांच के समय, उसके खिलाफ कोई बल प्रयोग नहीं किया गया प्रतीत होता है।मैं रोगी की उम्र के बारे में उसके सार्वजनिक बाल और जननांग आदि के विकास के आधार पर राय नहीं दे सकता। रोगी को यौन संभोग करने की आदत थी क्योंकि उसकी लैबिया मिनोरा हाइपरट्रॉफाइड थी और हाइमेन ने दो फिंगर को भर्ती किया था। "

4. इस स्तर पर, हमें यह उल्लेख करना चाहिए कि प्रासंगिक समय पर, यानी वर्ष 2000 में जब बलात्कार का कथित अपराध किया गया था, सहमति की आयु सोलह वर्ष और उससे अधिक थी।यह केवल वर्ष 2013 में किए गए एक संशोधन के माध्यम से किया गया था कि इसे बढ़ाकर अठारह वर्ष कर दिया गया है।न्यायालय में पेश किए गए स्कूल रजिस्टर से पता चलता है कि पीडब्लू-5 की जन्म तिथि 04.04.1987 है, जिससे घटना के समय अभियोजक की आयु केवल साढ़े 13 वर्ष हो जाएगी।हालाँकि, उसकी चिकित्सा जांच और डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजक की उम्र सोलह वर्ष है।इसके अलावा, स्वयं अभियोजक की माँ का संस्करण यह है कि अभियोजक सोलह वर्ष का था।

1 2013 का आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम No.13 दिनांक 3 फरवरी, 2013।

79

मानाक चंद @मणि बनाम हरियाणा राज्य [सुधानशु धूलिया, जे.] 80 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

5. बलात्कार के मामले में अभियोजक के साक्ष्य का मूल्य घायल गवाह के समान होता है।यह फिर से सच है कि अभियोजक की एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।फिर भी, जब कोई दोषसिद्धि अभियोजक की एकमात्र गवाही पर आधारित हो सकती है, तो अदालतों को भी इस एकमात्र गवाही की जांच करते समय बेहद सावधानी बरतनी होगी

पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह, (1996) 2 एस. सी. सी. 384 में चेतावनी दी गई:

“यदि अभियोजक का साक्ष्य विश्वास को प्रेरित करता है, तो भौतिक विवरणों में उसके बयान की पुष्टि किए बिना उस पर भरोसा किया जाना चाहिए।यदि किसी कारण से न्यायालय को

उसकी गवाही पर अंतर्निहित निर्भरता रखने में कठिनाई होती है, तो वह ऐसे सबूत की तलाश कर सकती है जो उसकी गवाही को आश्वासन दे सके, जो किसी साथी के मामले में आवश्यक पुष्टि से कम हो। अभियोजक की गवाही की पूरे मामले की पृष्ठभूमि में सराहना की जानी चाहिए और निचली विचारण न्यायालय को अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक होना चाहिए और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों से निपटने के दौरान संवेदनशील होना चाहिए। "

यह इस न्यायालय द्वारा सदाशिव रामराव हदबे बनाम राज्य मामले में दोहराया गया था।

महाराष्ट्र और एक अन्य (2006) 10 एस. सी. सी. 92:

"यह सच है कि बलात्कार के मामले में अभियुक्त को अभियोजक की एकमात्र गवाही पर दोषी ठहराया जा सकता है, यदि वह न्यायालय के मन में विश्वास पैदा करने में सक्षम है। यदि अभियोजक द्वारा दिया गया पक्ष किसी भी चिकित्सा साक्ष्य द्वारा असमर्थित है या आसपास की पूरी परिस्थितियाँ अत्यधिक असंभव हैं और अभियोजक द्वारा स्थापित मामले पर विश्वास करती हैं, तो न्यायालय अभियोजक के एकमात्र साक्ष्य पर कार्य नहीं करेगी। "

अभियोजक के साथ-साथ अभियुक्त दोनों को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, और इसलिए जब अभियोजक का बयान विश्वास को प्रेरित नहीं करता है और संदेह पैदा करता है, तो न्यायालय को पुष्टि करने वाले साक्ष्य की तलाश करनी चाहिए। गुरमीत सिंह (ऊपर) के मामले पर भरोसा करते हुए यह न्यायालय राजू में

और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2008) 15 एस. सी. सी. 133 निम्नानुसार अभिनिर्धारित है:

"10. उपरोक्त निर्णय इस मूल सिद्धांत को निर्धारित करते हैं कि आम तौर पर अभियोजक के साक्ष्य पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए और उस पर विश्वास किया जाना चाहिए, विशेष रूप से इसलिए कि उसके बयान का मूल्यांकन एक घायल गवाह के बराबर किया जाना चाहिए और यदि साक्ष्य विश्वसनीय है, तो किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। निस्संदेह, उपरोक्त टिप्पणियाँ

हम सम्मानपूर्वक उनसे सहमत हैं, लेकिन साथ ही उन्हें न्यायालय के समक्ष आने वाले यौन उत्पीड़न के प्रत्येक मामले के तथ्यों पर सार्वभौमिक और यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। 11. इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि बलात्कार पीड़ित के लिए सबसे बड़ी पीड़ा और अपमान का कारण बनता है, लेकिन साथ ही बलात्कार का एक झूठा आरोप आरोपी को भी उतना ही कष्ट, अपमान और नुकसान पहुंचा सकता है। अभियुक्त को झूठे निहितार्थ की संभावना से भी बचाया जाना चाहिए, विशेष रूप से जहां बड़ी संख्या में अभियुक्त शामिल हैं। इसके अलावा, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि व्यापक सिद्धांत यह है कि घटना के समय एक घायल गवाह मौजूद था और आम तौर पर ऐसा गवाह वास्तविक

हमलावरों के बारे में झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन यह मानने के लिए कोई अनुमान या कोई आधार नहीं है कि ऐसे गवाह का बयान हमेशा सही होता है या बिना किसी अलंकरण या अतिशयोक्ति के। "

6. क्या वर्तमान मामले में अभियोजक की गवाही विश्वास को प्रेरित करती है? हमें डर है कि ऐसा नहीं होगा। आइए हम एक बार फिर तथ्यों की सराहना करें। हालाँकि, बलात्कार की पहली घटना 12.09.2000 की होने का आरोप है, लेकिन अभियोजक तुरंत किसी को भी इसका खुलासा नहीं करता है। फिर वह दो या तीन अलग-अलग मौकों पर फिर से बलात्कार का आरोप लगाती है, हालाँकि कोई तारीख और समय का खुलासा नहीं किया जाता है। वह केवल डेढ़ महीने के बाद अपनी माँ को इस बारे में बताती है। इसके बाद अभियोजन पक्ष (पीडब्लू-2 यानी राम सहाय द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत स्कूल रजिस्टर में) के नेतृत्व में साक्ष्य में यह सामने आया है कि अभियोजक ने डबवाली में 12.09.2000 पर स्कूल में अपनी कक्षाओं में भाग लिया था, जहाँ वह अपने माता-पिता के साथ रहती है। हमें ध्यान देना चाहिए कि उसने उसी दिन गाँव सांवत खेरा में बलात्कार का आरोप लगाया है, जहाँ वह अपने वैवाहिक घर में अपनी बहन के साथ प्रासंगिक समय पर रह रही थी। यह असंभव नहीं तो असंभव लगता है। दूसरा पहलू स्वयं अभियोजन पक्ष की स्वीकार की गई स्थिति है कि अंततः प्राथमिकी दर्ज की गई क्योंकि विवाह के प्रारंभिक प्रस्ताव को तब अस्वीकार कर दिया गया था। ये सभी तथ्य अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह पैदा करते हैं।

7. अभियोजन पक्ष ने तब डॉ. कुलविंदर कौर द्वारा पीडब्लू-1 के रूप में दी गई अभियोजन पक्ष की चिकित्सा रिपोर्ट पर भी भरोसा किया है, जिसमें कहा गया है कि अभियोजन पक्ष का हाइमेन टूट गया था, और इसलिए उसके साथ बलात्कार किया गया था। इसके विपरीत जब हम उसी चिकित्सा रिपोर्ट की विस्तार से जांच करते हैं तो एक पूरी तरह से अलग तस्वीर सामने आती है। हालाँकि, विचारण न्यायालय ने सबूतों पर भरोसा किया 81

मानाक चंद @मणि बनाम हरियाणा राज्य [सुधानशु धूलिया, जे.] 82

अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन पक्ष की जन्म तिथि के संबंध में रखा गया, जिसे स्कूल रजिस्टर में 04.04.1987 के रूप में दर्ज किया गया था और इसलिए कथित अपराध के समय वह केवल साढ़े तेरह वर्ष की थी और इस प्रकार विचारण विचारण न्यायालय का निर्णय यह है कि, भले ही यह तर्क के लिए माना जाता है कि अभियोजन पक्ष यौन संभोग के लिए सहमति देने वाला पक्षकार था, उसकी सहमति महत्वहीन होगी क्योंकि वह सोलह वर्ष से कम उम्र की थी और इसलिए बलात्कार का आरोप साबित होता है। हालाँकि, अपील में उच्च न्यायालय ने अभियोजक के सहमति देने वाला पक्ष होने की धारणा को भी खारिज कर दिया और बलात्कार के संबंध में अभियोजक की गवाही पर पूरी तरह से भरोसा किया और अपील को खारिज कर दिया।

आयु या यहाँ तक कि बलात्कार के बारे में साक्ष्य की निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी ठीक से जांच नहीं की गई है। अदालतों को प्रत्येक साक्ष्य की खुले दिमाग से निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए क्योंकि एक आरोपी को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाना चाहिए। आपराधिक न्यायशास्त्र की हमारी प्रतिकूल प्रणाली में, मार्गदर्शक सिद्धांत हमेशा ब्लैकस्टोन अनुपात होगा जिसमें कहा गया है कि एक निर्दोष को दंडित करने की तुलना में दस दोषी व्यक्तियों का भाग जाना बेहतर है।

8. दो पहलू हैं जिन पर निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा अधिक विस्तार से विचार किया जाना चाहिए था। प्रथम अभियोजक की आयु है। अभियोजक की उम्र का मामले में बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अभियोजक को नाबालिग (सोलह वर्ष से कम आयु) ठहराने के लिए न्यायालय द्वारा एकमात्र सबूत सरकारी बालिका उच्च विद्यालय का स्कूल रजिस्टर है, जिसे स्कूल के क्लर्क राम सहाय (पीडब्लू-2) द्वारा न्यायालय में रखा गया था। निस्संदेह, स्कूल रजिस्टर में जन्म तिथि 04.04.1987 है जो घटना के समय अभियोजक को सोलह वर्ष से कम आयु का बनाता है। लेकिन राम सहाय (पीडब्लू-2) के साक्ष्य में यह भी आया है कि यह जन्म तिथि अभियोजक के माता-पिता के बयान पर नहीं, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई थी और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सरकारी प्राथमिक विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर आधारित थी, जहां जन्म तिथि 04.04.1987 के रूप में दर्ज की गई थी। फिर भी, यह स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसके आधार पर जन्म तिथि दर्ज की गई थी, कभी भी न्यायालय में पेश नहीं किया गया था। फिर भी, विचारण न्यायालय और हाई न्यायालय दोनों ने स्कूल रजिस्टर की सच्चाई पर भरोसा किया है। यह वही स्कूल रजिस्टर है जो स्कूल में 12.09.2000 पर अभियोजक की उपस्थिति को चिह्नित करता है। यह वह तारीख भी है जब अभियोजक था

/

[2023] 14 एस सी आर।

गाँव सांवत खेरा में अपीलार्थी के घर पर पहली बार कथित रूप से बलात्कार किया गया, जबकि स्कूल डबवाली मंडी नामक एक अन्य स्थान पर है। विचारण न्यायालय उसी स्कूल रजिस्टर में साक्ष्य को प्रामाणिक नहीं होने के रूप में खारिज कर देता है, जब बचाव पक्ष ने अभियोजक के एक ही समय में स्कूल में और सांवत खेरा गाँव में होने पर स्पष्ट विरोधाभास उठाए थे। यह सबूत की उचित सराहना नहीं है, कम से कम कहने के लिए, क्योंकि वही स्कूल रजिस्टर अभियोजक की उम्र के निर्धारण का एकमात्र आधार है।

9. यह न्यायालय बिराद मल सिंघवी बनाम आनंद पुरोहित (1988) संपं.

एस. सी. सी. 604 ने कहा था कि स्कूल के रजिस्टर में जन्म तिथि का कोई प्रामाणिक मूल्य नहीं होगा जब तक कि प्रवेश करने वाले व्यक्ति या जन्म तिथि देने वाले व्यक्ति की गवाही न हो।

“14. ...विद्वान के रजिस्टर में उल्लिखित जन्म तिथि का कोई प्रमाणिक मूल्य नहीं है जब तक कि प्रविष्टि करने वाले या जन्म तिथि देने वाले व्यक्ति की जांच नहीं की जाती है। प्रवेश प्रपत्र या छात्र रजिस्टर में निहित प्रविष्टि को माता-पिता या संबंधित व्यक्ति की जन्म तिथि के बारे में विशेष जानकारी रखने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर दिखाया जाना चाहिए। यदि जन्म तिथि के संबंध में विद्वान के रजिस्टर में प्रविष्टि माता-पिता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर की जाती है, तो प्रविष्टि का प्रमाणिक मूल्य होगा, लेकिन यदि यह किसी अजनबी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई है, जिसे जन्म तिथि की कोई विशेष जानकारी नहीं थी, तो ऐसी प्रविष्टि का कोई प्रमाणिक मूल्य नहीं होगा। ”

हमारी राय में, अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजक की आयु के संबंध में स्कूल रजिस्टर के रूप में प्रस्तुत किया गया प्रमाण इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था कि अभियोजक की आयु सोलह वर्ष से कम थी, विशेष रूप से जब अभियोजक की आयु के बारे में विचारण विचारण न्यायालय के समक्ष विरोधाभासी साक्ष्य थे। अभियुक्त को दोषी ठहराना न तो सुरक्षित था और न ही उचित, विशेष रूप से जब अभियोजक की उम्र मामले में इतना महत्वपूर्ण कारक था।

दूसरा, हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि चूंकि वर्तमान मामले में उम्र इतना महत्वपूर्ण कारक था, इसलिए अभियोजन पक्ष को अभियोजक की उम्र के निर्धारण के लिए अस्थि अस्थिकरण परीक्षण करना चाहिए था। वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया है। दूसरी ओर, नैदानिक 83 के अनुसार

मानाक चंद @मणि बनाम हरियाणा राज्य [सुधानशु धूलिया, जे.] 84

अभियोजक की जांच जो पीडब्लू-1, डॉ. कुलविंदर कौर द्वारा 28.10.2000 पर की गई थी और जिसका उल्लेख वर्तमान निर्णय के पूर्ववर्ती पैराग्राफ में भी किया गया है, हमें पता चलता है कि अभियोजक की माध्यमिक लिंग विशेषताएँ अच्छी तरह से विकसित थीं। डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि अभियोजक एक "अच्छी तरह से निर्मित वयस्क महिला" है। एक अन्य स्थान पर यह उल्लेख किया गया है कि "अच्छी तरह से विकसित जघन बाल" और "बाहरी जननांग पूरी तरह से विकसित और सामान्य थे"। यह तब उसकी उम्र को सोलह वर्ष के रूप में अभिलेख करता है जैसा कि अभियोजक की माँ ने उसे बताया था। रिपोर्ट में अभिलेख किया गया है कि उसके स्तन, गर्दन, चेहरे, पेट और जांघ पर चोट के कोई बाहरी निशान नहीं थे। रिपोर्ट तब निष्कर्ष निकालती है, अन्य बातों के साथ-साथ, उसकी उम्र के बारे में निम्नानुसार:

“रोगी की चिकित्सीय जांच के समय, उसके खिलाफ कोई बल प्रयोग नहीं किया गया प्रतीत होता है। मैं रोगी की उम्र के बारे में उसके जघन बाल और जननांग आदि के विकास के आधार पर राय नहीं दे सकता। रोगी को यौन संभोग करने की आदत थी क्योंकि उसकी लैबिया मिनोरा हाइपरट्रॉफाइड थी और हाइमेन ने दो फिंगर को भर्ती किया था। ”

डॉक्टर ने उम्र के बारे में खुद राय देने से परहेज किया है, लेकिन उसी रिपोर्ट में उम्र सोलह साल दर्ज की गई है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों अंतर्गत अभियोजक की उम्र के बारे में कुछ विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हड्डी ऑसिफ़ाई कैशन परीक्षण करने की आवश्यकता थी। जाहिर है कि ऐसा नहीं किया गया है। इसके अलावा, यह भी सबूत में आया है कि अभियोजक की मां ने भी कहा था कि उनकी बेटी सोलह साल की थी।

10. हमें एक अन्य प्रासंगिक कारक को भी ध्यान में रखना चाहिए। यह अभियोजक और अभियुक्त की सापेक्ष आयु होगी। संबंधित समय पर अभियुक्त की आयु 20 वर्ष से कम या लगभग 20 वर्ष थी, क्योंकि धारा 313 के अंतर्गत अपना बयान दर्ज करते समय उसकी आयु 20 वर्ष बताई गई है, जो कथित घटना के महीनों बाद है। तथ्य यह है कि अभियोजन पक्ष के पास एक मामला है कि शुरू में अपीलार्थी के साथ अभियोजन पक्ष के विवाह के प्रस्ताव को अपीलार्थी के परिवार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और केवल तभी जब अपीलार्थी ने विवाह से इनकार कर दिया कि प्राथमिकी अनिवार्य रूप से दर्ज की गई थी। ये सभी कारक इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि जिस पर बलात्कार का आरोप लगाया गया था वह बलात्कार नहीं था, बल्कि सहमति से किया गया कार्य हो सकता है। एकमात्र कारक जो सहमति के पहलू को महत्वहीन बना सकता था और इसे 'बलात्कार' का मामला बना सकता था, वह अभियोजक की उम्र थी। हालांकि, चिकित्सा साक्ष्य,

/

[2023] 14 एस सी आर।

वह बताती है कि उसकी उम्र 16 साल से अधिक है। अभियोजन पक्ष द्वारा डी. ओ. बी. को 04.04.1987 यानी स्कूल रजिस्टर के रूप में स्थापित करने के लिए रखा गया एकमात्र सबूत निर्णायक रूप से साबित नहीं हुआ है।

11. इन तथ्यों अंतर्गत और विचारण विचारण न्यायालय के समक्ष रखे गए साक्ष्य के भार के आधार पर, हमारी यह सुविचारित राय है कि अभियोजक की आयु के संबंध में, कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था। अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक यह साबित नहीं किया है कि कथित अपराध के समय अभियोजक की आयु सोलह वर्ष से कम थी, और इसलिए अपीलार्थी को लाभ दिया जाना चाहिए था। दूसरा, जहाँ तक बलात्कार के तथ्य का संबंध है, हम इस बात से आश्चस्त नहीं हैं कि इस मामले में बलात्कार की घटना सामने आई है क्योंकि यह भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 375 के अंतर्गत बलात्कार के घटकों को पूरा नहीं करता है, क्योंकि हम ऐसा कोई सबूत नहीं पाते हैं जो यह सुझाव दे कि अपीलार्थी ने अभियोजक के साथ यौन संबंध बनाए होने के बावजूद, यह उसकी इच्छा के खिलाफ या उसकी सहमति के बिना था।

12. नतीजतन, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च विचारण न्यायालय के दिनांकित 19.02.2014 आदेश और विचारण विचारण न्यायालय के दिनांकित 03.09.2001

आदेश को दरकिनार कर देते हैं।तदनुसार, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के आरोपों से बरी कर दिया जाता है। अपीलार्थी, जो जमानत पर है, को आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है।उनके जमानत बांड जारी किए जाते हैं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील अनुज्ञात ।

निधि जैन